will be taken up after the work on parallel Broad Gauge line between Dindigul and Madurai, at present in progress, is completed.

घाटे में चल रहे रेल मार्ग

552. **श्री राम नरेश यादव:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ऐसे कई रेल मार्ग हैं, जिन पर रेलवे को आर्थिक हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे रेल मार्गों की कुल संख्या कितनी है और क्या सरकार ने इन रेल मार्गों को आर्थिक रूप से लाभकारी बनाने के लिए कुछ प्रयास किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और ये प्रयास कब और किन मार्गों के लिए किए गए थे?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज): (क) से (ग) रेल मार्गों के वित्तीय परिणामों का ऐसा कोई आकलन नहीं किया जाता है। तथापि, शाखा लाइनों के वित्तीय संचालन का अध्ययन हर वर्ष किया जाता है। 1987-88 के लिए किये गये इस प्रकार के अध्ययन के परिणामों के आधार पर 145 शाखा लाइनें अलाभप्रद पायी गयी थीं।

अलाभप्रद शाखा लाइनों की आमदनी बढ़ाने और संचालन व्यय को यथा संभव कम करने के लिए समय-समय पर निम्नलिखित उपाय किये जाते हैं:—

1. ऐसी गाड़ियों को रद्द करना जिनमें बहुत कम संख्या में यात्री यात्रा करते हैं।

2. अलाभप्रद स्टेशनों/हाल्टों को बन्द करना अथवा उन्हें ठेकेदार द्वारा परिचालित हाल्ट में बदलना।

3. यात्री और माल गाड़ियों के स्थान पर मिश्रित गाड़ियां चलाना।

4. "केवल एक इंजन" प्रणाली लागू करना।

5. कर्मचारियों की संख्या में कटौती।

6. खंड पर बिना टिकट यात्रा की रोकथाम।

"रेनफेड एग्रीकल्चर प्लान : स्टेट्स टोल्ड टू स्पीड अप प्रोपोजल्स" शीर्षक से समाचार

553. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 अक्तूबर, 1989 के "दि फाइनेंशियल एक्सप्रेस" में "रेनफेड एग्रीकल्चर प्लान: स्टेट्स टोल्ड टू स्पीड अप प्रोपोजल्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार को अब तक ऐसे किन-किन राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं जिनसे इस योजना के अधीन प्रस्ताव आमंत्रित किये गये थे?

उप-प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल): (क) और (ख) जी, हां। सभी 16 राज्यों ने 1989-90 के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए हैं और वर्षा सिंचित खेती के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास कार्यक्रम को केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजना कार्यान्वयन करने हेतु केन्द्रीय भागीदारी भी निर्मुक्त की गई है।

झुग्गी-झोपड़ी-निवासियों की सामूहिक आवास समितियों को भूमि का आवंटन

554. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के निवर्तमान उपराज्यपाल ने माह जुलाई, 1989 में जीवन-यापन की बेहतर स्थिति के लिए दिल्ली के झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों से सामूहिक आवास समितियां बनाने का आग्रह किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण वर्ष 1983 में गठित की गई सामूहिक आवास समितियों को भूमि का आवंटन नहीं कर पाया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों की सामूहिक आवास समितियों को भूमि आवंटन करने के लिए कोई योजनाएं बनाई है; यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

दिल्ली में गन्दी बस्तियों के विकासार्थ धनराशि का कम उपयोग

555. **श्री राम जेठमलानी:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान गन्दी-बस्तियों के विकासार्थ धनराशि के कम उपयोग के संबंध में दिनांक 11 अगस्त, 1989 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "स्लम फन्डस वेयर नोट यूज्ड फुल्ली" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि प्रशासन दिल्ली की गन्दी

बस्तियों वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के कल्याणार्थ आवंटित धनराशि को व्यय करने में विफल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार, इस प्रयोजनार्थ कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई थी तथा उक्त अवधि के दौरान, वर्ष-वार उक्त प्रयोजनार्थ वास्तव में कितनी धनराशि व्यय की गई थी तथा इस प्रकार के कु-प्रबन्ध के क्या कारण थे?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

झुग्गी-झोंपड़ियों संबंधी सर्वेक्षण-प्रतिवेदन

556. **श्री रामनरेश यादव:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में झुग्गी-झोंपड़ियों के संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पिछले वर्ष एक सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उस सर्वेक्षण का विस्तृत प्रतिवेदन क्या है तथा दिल्ली में किन-किन स्थानों पर ऐसी झुग्गी-झोंपड़ियां बनी हुई हैं और उनमें कितने व्यक्ति रह रहे हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों को पेयजल, बिजली, जल-मल निकास प्रणाली जैसी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी थीं; और

(घ) यदि हां, तो ये सुविधाएं अभी तक किन-किन क्षेत्रों में उपलब्ध करायी गयी हैं?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) यमुना नदी के पश्चिम में स्थित झुग्गी-झोंपड़ियों के समूहों का एक सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण से पता लगा कि वहां 457 झुग्गी-झोंपड़ी समूह थे, जिनमें कुल 1,27,460 झोपड़ियां थीं तथा उनकी जनसंख्या 457224 है, जिनमें से 57.72 प्रतिशत पुरुष एवं 42.78 प्रतिशत स्त्रियां थीं। झुग्गी-झोंपड़ी समूहों को दर्शाने वाली सूची तथा झुग्गियों की संख्या और प्रत्येक झुग्गी समूह में रहने वालों की जनसंख्या अनुलग्नक में दी गई है। [देखिये परिशिष्ट 152, अनुपत्र सं० 25]

(ग) और (घ) पेयजल, परिधीय पथ प्रकाश "भुगतान करो एवं उपयोग करो" जनसुविधा परिसर, जिसमें शौचालय, स्नानागार, कूड़ा-करकट जमा करने के लिए ढलाव/कूड़ेदान, गलियों में ईंटें बिछाना तथा नालियां बनाने जैसी न्यूनतम मूलभूत सुविधा की आवश्यकताओं का जहां भी स्थानीय परिस्थितियों अनुमेय करती हैं, वहां विस्तार किया जाता है। झुग्गी-झोंपड़ी समूह की पर्यावरणीय सुधार योजना के अन्तर्गत सुविधायें, जो उपलब्ध कराई गई हैं या उपलब्ध कराई जा रही हैं, का विवरण निम्न प्रकार है:—

(1) **जनसुविधा परिसर:**

(क) 117 परिसर, जिनमें 5588 डब्लयू सी सीटें तथा 2356 स्नानागार हैं।

(ख) 14 जनसुविधा परिसरों का कार्य प्रगति पर है।

(2) **विद्युत:**

326 झुग्गी समूहों में 4981 विद्युत पोल लगाये गये, जिनसे 6318 पथ-प्रकाश प्वाइंट उपलब्ध कराये गये हैं।

(3) **जलपूर्ति:**

(क) 216 झुग्गी समूहों में 601 इण्डिया पार्क 11 गहरे हैण्ड पम्प उपलब्ध कराये गये हैं।

(ख) पानी के नल: 280 झुग्गी-झोपड़ी समूहों में 917 नल लगाए गए हैं।

(4) **ईंटें बिछाना तथा नालियां :**

(क) 133 झुग्गी समूहों की गलियों में ईंटें तथा नालिया बनाई गई हैं।

(ख) 171 समूहों में कार्य प्रगति पर है।

कृषक-शिकायत पैनलों की स्थापना

557. **श्री राम नरेश यादव:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान कृषक-शिकायत पैनल की स्थापना के संबंध में 6 सितम्बर, 1989 को प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार द्वारा किसी ऐसी समिति की स्थापना की गई है जो किसानों की समस्याओं के समाधान में सहायक हो सके; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

उप-प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल): (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस समय सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।